सरकारी क्षेत्र की अपने नियत समय से पीछे चल रही परियोजनाएं

1739. **श्री रणजीत सिंह :**
डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1991 तक सरकारी क्षेत्र की कुल कितनी परियोजनाएं अपने नियत मूल समय सीमा से पीछे चल रही थीं;

(ख) प्रत्येक मंत्रालय से सम्बद्ध कितनी-कितनी परियोजनाएं हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन परियोजनाओं को समय से पूरा नहीं किये जाने के कारण इनकी निर्माण लागत में भारी वृद्धि हो गई है;

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक मंत्रालय के अधीन आने वाली विभिन्न परियोजनाओं के सम्बन्ध में ऐसी कितनी-कितनी वृद्धि हुई है; और

(ङ) इन सभी परियोजनाओं को मूल समय-सीमा के अधीन पूरा नहीं किये जाने के कारण देश को कुल कितनी आर्थिक क्षति होने की संभावना है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) 31.12.1991 की स्थिति के अनुसार, 189 केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाएं, जिनकी प्रत्येक की लागत 20 करोड़ रुपये से अधिक है और कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग द्वारा प्रबोधित की जा रही है, अपने मूल समय सीमा से पीछे चल रही थीं।

(ख) इन 189 परियोजनाओं का मंत्रालय/क्षेत्र-वार विघटन संलग्नक विवरण पत्र में दिया गया है। **(नीचे देखिए)**

(ग) और (घ) इन विलम्बित परियोजनाओं की निर्माण लागत में वृद्धि के अनेक कारण हैं। लक्षित समय सीमा के भीतर पूरा होने में असफलता के कारण इन परियोजनाओं की निर्माण लागत में वृद्धि को अलग से मूल्यांकन करना संभव नहीं है।

(ङ) इन सभी परियोजनाओं के समय सीमा के अधीन पूरा नहीं किए जाने के कारण देश को जो अर्थिक क्षति होने की संभावना है, उसका परिमाणन करना संभव नहीं है।

विवरण

मूल स्वीकृत राशि के संबंध में विलम्बित केन्द्रीय परियोजनाओं, जिनकी प्रत्येक की लागत 20 करोड़ रुपये से अधिक है और कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के प्रबोधनाधीन है, में 31 दिसम्बर, 91 की लागत वृद्धि की स्थिति :

सं०	क्षेत्र/मंत्रालय	विलम्बित परियोजनाओं की कुल सं.	मूल स्वीकृत लागत करोड़ रुपये	नवीनतम प्रत्याशित लागत करोड़ रुपये	लागत वृद्धि करोड़ रु०
1	2	3	4	5	6
1.	परमाणु ऊर्जा	5	2456.3	6626.3	4170.0
2.	नागर विमानन	1	958.8	1070.3	111.5
3.	कोयला	35	3277.2	6610.4	3333.2
4.	उर्वरक	1	183.6	630.8	447.2
5.	सूचना और प्रसारण	3	167.4	244.6	77.2

1	2	3	4	5	6
6.	खान . . .	0	0.0	0.0	0.0
7.	इस्पात और खनिज लोहा .	5	6139.2	15069.7	8930.5
8.	रसायन तथा पट्रो रसायन .	3	1294.9	1844.2	549.3
9.	पैट्रो तथा प्राकृतिक गैस .	17	3681.6	4664.4	982.8
10.	विद्युत . . .	32	14453.7	26571.5	12117.8
11.	उद्योग (कागज, सिमेंट तथा आटो इत्यादि) . . .	6	762.1	1393.0	630.9
12.	रेलवे . . .	44	2247.6	5428.2	3180.6
13.	भूतल परिवहन . .	21	1663.4	2726.1	1062.7
14.	दूर संचार . .	16	603.6	729.0	125.4
	कुल . . .	189	37889.4	73608.5	35719

Number of Projects identified for Completion

1740. SHRI RANJIT SINGH:
DR. JINENDRA KUMAR JAIN:

Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item appearing in "The Hindu" of 19th December, 1991 under the caption "On going projects for nearly Rs. 4,00,000 crore";

(b) if so, the total number of projects that have been identified for completion in the forthcoming years;

(c) what are the estimates about the periods and the amount of money required for completion of these projects;

(d) whether special measures and vigilance is being undertaken by Government to complete these projects within the targetted period; and

(e) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI H. R. BHARDWAJ): (a) Yes, Sir. The news item to which the Hon'ble Member has drawn attention relates to investment costs of all on-going projects in Central States, Joint Sector and private Sectors. As per this sources, nearly 60 per cent relates to on-going projects of the Public Sector, of which Central Sector accounts for 33.2 per cent and State Sector accounts for 26.6 per cent.

(b) and (c) As per the monitoring system of Department of Programme Implementation, as on 31st December 1991, there were 307 Central projects each costing over Rs. 20 crores under implementation in 14 sectors of the economy. The anticipated cost of completion of these projects is Rs. 94511.5 crores. Of these, 273 projects are anticipated to be completed by November, 1999. The date of completion of the remaining 34 projects is yet to be firmed up.

(d) and (e) Yes, Sir. Besides the close monitoring of these projects by the concerned Administrative Ministries|Departments these projects are